



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 23, 1944 शक संवत) [संख्या 42

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	3075	841-851	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-क— नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1500	843-875	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1-ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का 199-210 क्रोडपत्र, खण्ड के—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड घ—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7-ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुचित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के ऑकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के ऑकड़े, फसल और ऋतु, सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	487-497	975
			स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

04 जुलाई, 2022 ई०

सं० 352 / दो-४-२०२२-संयुक्त निबन्धक, एडमिन (A-1 & A-4) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संया 7463/IV-3812/एडमिन, (A), दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा श्री सुदेश कुमार तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मलिहाबाद, लखनऊ सम्पति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद मुरादाबाद के स्थान पर सम्भल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

संयुक्त निबन्धक, एडमिन (A-1 & A-4) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 10 जून, 2022 के क्रम में एम०जी०३०० के प्रस्तर-३१ में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरांत श्री सुदेश कुमार, तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मलिहाबाद, लखनऊ सम्पति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद मुरादाबाद के स्थान पर सम्भल परिवर्तित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं० 359 / दो-४-२०२२-२६ / २(५) / २०११—उप निबन्धक, (Admin Misc.-1) संयुक्त निबन्धक (A-1 & A-4) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल०एल०एम० डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र०	न्यायिक अधिकारी का सं० नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम०)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-I) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5

सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री—

1	सुमित कुमार, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, मथुरा	7552 / IV-4520 / Admin. (A-1) दिनांक 14-06-2022	चौधरी चरण सिंह	एल०एल०एम० 2018
2	ज्योति अग्रवाल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर	7550 / IV-4110 / Admin. (A-1) दिनांक 14-06-2022	कुरुक्षेत्र	एल०एल०एम० 2020
3	खुशबू चन्द्रा, जुड़िशियल मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद	7616 / IV-5127 / Admin. (A-1) दिनांक 16-06-2022	विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	आई०आई०एम०टी० एल०एल०एम० 2019

16 अगस्त, 2022 ई०

सं० 574 / दो-४-२०२२-२६ / २(५) / २०११—संयुक्त निबन्धक, (Admin (A-१ & A-४) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल०एल०एम० डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र०	न्यायिक अधिकारी का सं० नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम०)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-१) मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री/ श्रीमती/ सुश्री—					
1	अभिषेक कुमार, सिविल जज (जू०डि०), बस्ती	9333/IV-5280/Admin. (A-1) दिनांक 30-07-2022	श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ	एल०एल०एम०	2018
2	अनुल कुमार नायक, सिविल जज (जू०डि०), बस्ती	9331/IV-4671/Admin.(A-1) दिनांक 30-07-2022	स्वामी विवेकानन्द यूनिवर्सिटी, सागर, मध्य प्रदेश	एल०एल०एम०	2014

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग-४

नियुक्ति

29 जुलाई, 2022 ई०

सं० 55रा०/22-७/५/2020-सी०एक्स०-४—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम १६ (१) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री सैय्यद आसिफ कमाल, अनुभाग अधिकारी को दिनांक ०१ जुलाई, 2022 के पूर्वान्ह से अनु सचिव के रिक्त पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-११ (रु० ६७,७००-२,०८,७००) पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं० 56रा०/22-७/५/2020-सी०एक्स०-४—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम १६ (१) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री इन्द्र सेन, समीक्षा धिकारी को दिनांक ०१ जुलाई, 2022 के पूर्वान्ह से अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद

वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु० ५६,१००-१,७७,५००) पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं० ५७रा०/२२-७/५/२०२०-सी०एक्स०-४—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमाबली, १९८६ (यथासंशोधित) के नियम १६ (१) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री कमलेश कुमार, समीक्षा धिकारी को दिनांक ०१ जुलाई, २०२२ के पूर्वान्ह से अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु० ५६,१००-१,७७,५००) पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

[पुलिस सेवाये]

अनुभाग-१

प्रोन्नति

२५ अगस्त, २०२२ ई०

सं० १५६९ / छःपु०से०-१-२०२२-डौ०पी०सी०(एच०एल०) / २०२१—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु० ३७,४००-६७,०००, ग्रेड-पे रु० ८,९००, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-१३क, रु० १,३१,१००-२,१६,६००) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक १७ अगस्त, २०२२ में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, उच्च वेतनमान (वेतनमान ३७,४००-६७,०००, ग्रेड पे-१०,०००) (पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स-१४, रु० १,४४,२००-२,१८,२००) में प्रोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
१	२	३	४
सर्वश्री—			
१	रमेश प्रसाद गुप्ता	९५	१९९२
२	केशव चन्द्र गोस्वामी	९७	१९९२

२—उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों/परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियाँ जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थगित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

३—उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

४—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1570 / छ.पु०से०-१-२०२२-डी०पी०सी०(एस०एल०-१) / २०२१—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु० ३७,४००-६७,०००, ग्रेड-पे रु० ८,७००, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-१३, रु० १,२३,१००-२,१५,९००) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक १७ अगस्त, २०२२ में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान ३७,४००-६७,०००, ग्रेड पे-८,९००, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-१३क, रु० १,३१,१००-२,१६,६००) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द मिश्र	125	1993

2—उपर्युक्त प्रोन्नति अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं० 1571 / छ.पु०से०-१-२०२२-डी०पी०सी०(एस०एल०-२) / २०२१—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु० १५,६००-३९,१००, ग्रेड-पे रु० ७,६००, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-१२, रु० ७८,८००-२,०९,२००) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक १७ अगस्त, २०२२ में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान ३७,४००-६७,०००, ग्रेड पे-८,७००, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-१३, रु० १,२३,१००-२,१५,९००) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
सर्वश्री—			
1	राम मोहन सिंह	195	1996
2	रोहित मिश्रा	196	1996
3	शिवराम यादव	197	1996

2—उपर्युक्त प्रोन्नति अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग-2
कार्यालय-आदेश
06 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 331/छ.पु०से०-२-२२-५२२(१९)/२०२२—गृह विभाग के अधीन आईपीएस अधिकारियों के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी का पद समाप्त करते हुये पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ग्रामीण, कानपुर आडटर एवं वाराणसी ग्रामीण पद के सृजन के साथ-साथ निम्नवत् पद सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र०	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	संगठन/इकाईचार
१	२	३	४
१	अपर पुलिस महानिदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-१५ (1,82,200-2,24,100)	३	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-०२, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-०१
२	पुलिस महानिरीक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल-१४ (1,44,200-2,18,200)	३	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-०२, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-०१
३	पुलिस उप महानिरीक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल-१३ए (1,31,100-2,16,600)	६	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-०२, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-०४
४	पुलिस अधीक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल-१० (56,100-1,77,500)	३२	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-०२, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-११ साइबर क्राइम थाना-०१, ऐटौ०एस० का सुदृढ़ीकरण-०२+०१

२—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या ई-१२-१५१ (ई०ओ०)/दस-२०२२, दिनांक ०४ अप्रैल, २०२२ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1
कार्यालय-ज्ञाप

०३ अगस्त, २०२२ ई०

सं० ८३४/२२-पच्चीस-१-७/२/७/९५-सी०एक्स०(१)—मा० न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार गुप्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
१	२
१	दिनांक २७ जनवरी, २०२१ से २९ जनवरी, २०२१ तक ०३ (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
२	दिनांक ०१ फरवरी, २०२१ से ०५ फरवरी, २०२१ तक ०५ (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेषसचिव।

11 अगस्त, 2022 ई०

स० 977 / 22-पच्चीस-1-6 / 2 / 3 / 2013-सी०एक्स०(1)-(1) श्री सौरभ श्रीवास्तव तथा (2) श्री ओम प्रकाश शुक्ला, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2022 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

सेवा-निवृत्ति

21 जनवरी, 2022 ई०

स० आडिट-1-134526 / दस-2022-सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2022 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर, अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो जायेगे—

क्र०	कोटि	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म-तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
सं०	क्रमांक				
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री—					
1	1	अवनीन्द्र दीक्षित	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	12-04-1962	30-04-2022
2	4	कृष्णपाल	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	15-05-1962	31-05-2022
3	19	दीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	19-01-1962	31-01-2022
4	25	उमाशंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	30-06-1962	30-06-2022
5	27	विजय शंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	25-08-1962	31-08-2022
6	37	रामनिवास मिश्र	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	03-08-1962	31-08-2022
7	45	हरि नारायण मिश्र	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	08-12-1962	31-12-2022
8	57	सत्य प्रकाश द्विवेदी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	07-04-1962	30-04-2022
9	59	विश्वनाथ वर्मा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	25-09-1962	30-09-2022
10	697	अशोक कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15-01-1962	31-01-2022
11	728	सुरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	03-06-1962	30-06-2022

आज्ञा से,
सजय कुमार,
सचिव।

प्रोल्लासि

31 अगस्त, 2022 ई०

सं० आडिट-1-207103 / दस-2022-उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये श्री राज्यपाल द्वारा उ०प्र० सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करते हुये उन्हें उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4
सर्वश्री-			
1	सुशील कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, फरुखाबाद	देवीपाटन मण्डल
2	विजय शंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, संतकबीर नगर	मुख्यालय लखनऊ
3	आनन्द प्रकाश पाठक	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कन्नौज	आजमगढ़ मण्डल

2-सम्बन्धित अधिकारी अपने पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
नितिन कुमार गुप्त,
अनु सचिव।

[वित्त सेवायें]

अनुमान-1
सेवा-निवृत्ति

04 अगस्त, 2022 ई०

सं० 1 / 198426 / 2022-राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत श्री अरुण प्रकाश द्विवेदी, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

सं० 1 / 198737 / 2022-राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत श्री विनय कुमार, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत, निदेशालय, उ०प्र० 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2023 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
मोहम्मद शाहिद,
विशेष सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]
सेवा-निवृत्ति

01 अगस्त, 2022 ई०

सं० 1889(1) / वि०प्र०-267 / 84-श्री विजेन्द्र सिंह, निजी सचिव, श्रेणी-1, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 जुलाई, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

नियुक्ति

04 अगस्त, 2022 ई०

सं० 1916(1)वि०प०-२०/१२—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के रिक्त विशेष सचिव के अस्थायी पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100-2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-६ (1-ख) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-३० (क) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री विजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव को विशेष सचिव के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100-2,16,600) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं० 1917(1)वि०प०-२०/१२—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के विशेष सचिव के पद पर श्री विनय कुमार सिंह की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये संयुक्त सचिव के पद पर उत्तर प्रदेश परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019, नियम-६ (1-ख) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली 1976 के नियम-३० (क) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री राम सागर शुक्ल, उप सचिव को संयुक्त सचिव के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

डॉ राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-४

पदोन्नति

20 जनवरी, 2022 ई०

सं० 48/11-४-2022-३०(१२)/२१—वाणिज्य कर विभाग में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१, वाणिज्य कर के पद कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण के पद पर (वेतनमान रु० 37,400-६७,००० एवं ग्रेड वेतन रु० 10,000 पे मैट्रिक्स लेवल-१४) एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
१	२	३
सर्वश्री—		
१	नारायण कुमार अग्रवाल	1018
२	असफाक अहमद	1127

२—उक्त पदोन्नत अधिकारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण के कार्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

३—उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग-१

25 जनवरी, 2022 ई०

सं० राज्य कर-१-१२४/११-२०२२-०८/२०२१—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु० 15,600-३९,१०० ग्रेड पे रु० 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-१०) को वर्तमान पद पर कार्यभार

ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	2491	सर्वश्री/सुश्री— आशीष शुक्ला
2	2493	श्वेता तोमर

सं० राज्य कर-1-125 / 11-2022-07 / 2021—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु० 15,600-39,100 ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11)) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे रु० 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	1895	सर्वश्री— सूर्यकान्त तिवारी
2	1896	विजय कुमार झा

सं० राज्य कर-1-126 / 11-2022-06 / 2021—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु० 15,600-39,100 ग्रेड पे रु० 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12)) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु० 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके एडीशन कमिश्नर ग्रेड-2 के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे—

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
1	1414	सर्वश्री/श्रीमती— रुबी सिंह-I
2	1415	राम प्रवेश प्रसाद
3	1416	दीनानाथ
4	1418	राजेश कुमार-V
5	1421	विजय प्रकाश राम
6	1426	राम प्रकाश-III

तैनाती

07 अप्रैल, 2022 ई०

सं० राज्य कर-1-452 / 11-2022-22 / 2022—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर (वेतनमान रु० 37,400-67,000 ग्रेड पे रु० 8,700 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13)) को कार्यभार ग्रहण

करने की तिथि से वेतनमान रु० 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु० 8,900 (पै मैट्रिक्स लेवल-13क) में एतदद्वारा पदोन्नति प्रदान करते हुये निम्न तालिका के कालम 4 मे अकित रिक्त पद/स्थान पर तैनात किया जाता है-

क्र०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
स०			
1	2	3	4
सर्वश्री/ श्रीमती			
1	सत्यपाल सिह ॥	एडीशनल कमिशनर ग्रेड 2 (अपील) 2, गोरखपुर	एडीशनल कमिशनर ग्रेड 1 वाणिज्यकर सहारनपुर
2	गुना सिह बौनाल	एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (अपील) चतुर्थ गाजियाबाद	एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्यकर कानपुर-प्रथम
3	गाविन्द सिह बुद्धियाल	एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (अपील) 1 गोरखपुर	एडीशनल कमिशनर ग्रेड 1 वाणिज्यकर गाजियाबाद प्रथम
4	सुनील कुमार राय	एडीशनल कमिशनर ग्रेड 2 वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ	एडीशनल कमिशनर ग्रेड 1 वाणिज्यकर गोरखपुर
5	ज्योत्सना पाण्डेय	एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (अपील), बुलन्दशहर	एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 वाणिज्यकर, प्रयागराज
6	रवीन्द्र नाथ शुक्ला	एडीशनल कमिशनर ग्रेड 2 (अपील), पचम कानपुर	एडीशनल कमिशनर ग्रेड 1 वाणिज्यकर अलीगढ़।

आज्ञा से
सजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

17 जून 2022 ई०

स० रा०क० १ ६५१ / ११ २०२२ ९७३(३) / २०२२ श्रीमती भावना अग्रवाल असिस्टेन्ट कमिशनर सचल दल चतुर्थ इकाई राज्य कर गाजियाबाद को आयुक्त राज्य कर ३०प्र० लखनऊ के कार्यालय से एतदद्वारा सम्बद्ध किया जाता है-

2 उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पदोन्नति

०६ जुलाई, २०२२ ई०

स० राज्य कर १ ८५९ / ११ २०२२-०८ / २०२१ राज्य कर विभाग के निम्नलिखित सहायक आयुक्त राज्य कर (वेतनमान रु० 15,600-39,100 ग्रेड रु० 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-१०) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु० 15,600-39,100 ग्रेड पे रु० 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-११) एतदद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है इनके उपायुक्त, राज्य कर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे-

क्र०	स०	पदोन्नति क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3	4
सर्वश्री/ सुश्री-			
1	2506	अजुमन निकहत जाफरी	
2	2507	अलका श्रीवास्तव	

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०य०पी०-२९ हिन्दी गजट-भाग १-२०२२ ई०

मुद्रक एवं प्रकाशक-निदेशक मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज।



सरकारी गज़ाट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 23, 1944 शक संवत्)

माग 1-क

नियम, कार्य विधिया आज्ञायें विज्ञापिया इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञापियां

06 अक्टूबर, 2022 ई०

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत)

स० 132/आ०जि०भ०आ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2 × ६६०मे०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम रामपुर घनश्यामपुर में स्थित ०६८४० हेठो भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक ९७२०/आ०जि०भ०आ०/आगरा दिनाक ०९ जून, २०२२ को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक ०२ अगस्त २०२२ को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक ०६ अगस्त २०१४ के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम रामपुर घनश्यामपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापित कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
एटा	एटा	एटा सकीट	रामपुर घनश्यामपुर	120	0 0053
				121	0 0023
				122	0 0 20
				119	0 326
				123 स	0 1471
				113	0 1772
				114	0 0140
				योग	0.6840

अनुसूची ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी - उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2 × ६६०मेओवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम रामपुर घनश्यामपुर में स्थित ०.६८४० हेतु भूमि के लिये प्रकाशित ९७२०/अ०जि०भू०३०/आगश दिनाक ०९.०६.२०२२ के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है-

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट)
कलेक्टर, एटा

NOTIFICATION

October 06, 2022

[Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act]

No. 132 A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no. 9720.ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.6840 hectares of land in the villages Rampur Ghanshyampur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02/08/2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L.A)submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Rampur Ghanshyampur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE A**(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)**

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Etah	Etah	Etah Sakeet	Rampur Ghanshyampur	120	0.0053
				121	0.0023
				122	0.0120
				119	0.3261
				123 स	0.1471
				113	0.1772
				114	0.0140
				Total .	0.6840

SCHEDULE-B**(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation (in hect)
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition

Notification of Declaration by Collector
[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9720 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0.6840 hectares of land in villages Rampur Ghanshyampur Pargana Etah Sakeet Tehst. Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं० 133/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 x 660में०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क" हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम-चाचरमऊ मेरि स्थित 0.0267 हेठु भूमि के सम्बन्ध मेरि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मेरि उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9717/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09 जून 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02 अगस्त 2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधिकों के अनुपालन मेरि कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य मेरि धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निर्देश दत्ते हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" मेरि वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" मेरि उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम चाचरमऊ की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप मेरि चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निर्देश दत्ते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापित कलेक्टर को निर्दिशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सख्ता	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
एटा	एटा सकीट	एटा सकीट	चाचरमऊ	2	0.0260
				104	0.0007
				योग	0.0267

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप मेरि चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सख्ता	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
				शून्य	

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय मेरि देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की घारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2 × 660मेओवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम-वाचरमऊ में स्थित 0.0267 हेक्टर भूमि के लिये प्रकाशित 9717 / आजि0भू0अ0 / आगरा दिनांक 09 जून, 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है

परियोजना से प्रभावित भू स्थानी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह0 (अस्पष्ट)

कलेक्टर, एटा

No. 133/A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no. 9717 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0267 hectares of land in the villages Chacharmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02/08/2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Chacharmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Etah	Etah	Etah Sakeet	Chacharmau	2	0.0260
				104	0.0007
				Total. .	0.0267

SCHEDULE-B**(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector**[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]**

By the order of declaration made under Government notification no 9717 ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0267 hectares of land in villages **Chacharmau** Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Therma Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector Etah

स० 134/अ०जि०भ०अ०/आगरा-जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2 X 660मेंवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा स्कीट व तहसील एटा ग्राम-निगोहसनपुर में स्थित 00813 हेठु भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9708/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09 जून 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02 अगस्त 2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2, के प्राविधिकों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिषेष में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा स्कीट ग्राम निगोहसनपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2 के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापिति कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
एटा	एटा सकीट	एटा सकीट	निगोहहसनपुर	260	0 0036
				176	0 0589
				1340 स	0 0040
				28 स	0 0037
				185 स	0 0111
				योग. .	0.0813

अनुसूची ख

(विस्थापित परियारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थल नक्शा क्लेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्लेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा 2×860 में ० वाट जवाहरपुर तारीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम निगोहहसनपुर में स्थित 0.0813 हेतु भूमि के लिये प्रकाशित 9708/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा क्लेक्टर एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट)

क्लेक्टर, एटा

No. 134/A.D.M.(L.A.)Agra—Whereas Preliminary notification no 9708 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 1. of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0813 hectares of land in the villages Nigohhasanpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Nigohhasanpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Etah	Etah Sakeet	Etah Sakeet	Nigohhasanpur	260	0.0036
				176	0.0589
				1340 स	0.0040
				28 स	0.0037
				185 स	0.0111
				Total..	0.0813

SCHEDULE- B (Land Identified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector
[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9708 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0.0813 hectares of land in villages Nigohhasanpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Therma Power Project through awaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector Etah.

सठ 135/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा “2X660मेंवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम शीतलपुर में स्थित 0.0748 हेतु भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9722/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्णय की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा का परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपनन शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिषेक्ष्य में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम शीतलपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापित कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
एटा	एटा सकीट	एटा सकीट	शीतलपुर	17	हेक्टेयर 0.0748
				योग.	0.0748

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
				शून्य	

टिप्पणी:-उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
(अधिनियम की घारा-१९ की उपधारा (2) के अन्तर्गत)**

जयाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2X660मेओवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क' हेतु जनपद एटा परगना एटा स्कीट व तहसील एटा, ग्राम-शीतलपुर में स्थित 0.0748 हेक्टर भूमि के लिये प्रकाशित 9722/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है

परियोजना से प्रभावित भू-स्थानी लघु कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट),

कलेक्टर, एटा

No. 135/A.D.M.(L.A.)Agra-Whereas Preliminary notification no 9722.ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0748 hectares of land in the villages Sheetalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(.) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Sheetalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section .9 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

**SCHEDULE-A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)**

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Etah	Etah	Etah Sakeet	Sheetalpur	17	0.0748
				Total .	0.0748

**SCHEDULE-B
(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
				Nil	

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9722/ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0.0748 hectares of land in villages Sheetalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of Small farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition

*(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector Etah*

स० 136/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मेंवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलाबन, एटा के एटा से मलाबन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम-एटा देहात मे स्थित 0.6432 हेक्टर भूमि के सम्बन्ध मे भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रायमिक 9710/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा का परियोजना प्रभावित परिवास के पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम एटा देहात की शून्य भूमि को विस्थायित परिवासों के पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापिकलेक्टर को निर्दिशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	एटा देहात	314	0.0066
				346	0.0004
				349	0.0087
				533/2	0.6275
				घोग	0.6432

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की घारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2X660में0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क' हतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम एटा देहात में स्थित 0.6432 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित 9710/अ०जि०भ०३०/आगरा दिनाक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है।

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त/लघु कृषक की श्रेणी में आत है

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा

No. 136/A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no 9710.ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.6432 hectares of land in the villages Etah Dehat Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector (LA) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Etah Dehat Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Etah	Etah	Etah Sakeet	Etah Dehat	314	0 0066
				346	0 0004
				349	0 0087
				533/2	0 6275
				Total..	0.6432

SCHEDULE- B
(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9710/ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0 6432 hectares of land in villages Etah Dehat Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below

Land affected by project comes under the category of marginal/small farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

स० 137/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 × 660मे०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम लालगढ़ी मे० स्थित 0.0272 ह० भूमि के सम्बन्ध मे० भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्बृद्धिस्थापन मे० उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की घारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9711/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनांक 09-06-2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02-08-2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्बृद्धिस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपक्ष में धारा-19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम लालगढ़ी की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2), के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापित कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
एटा	एटा	एटा सकीट	लालगढ़ी	874	0 0272
				योग.	0.0272

अनुसूची ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिई के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660में0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क" हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम लालगढ़ी में स्थित 0 0272 हेतु भूमि के लिये प्रकाशित 9711/अ०जि०भ००/आगरा दिनाक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है।

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट)

कलेक्टर एटा

No. 137/A.D.M.(L.A.)Agra—Whereas Preliminary notification no 9711 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0 0272 hectares of land in the villages Lalgarhi Pargana Etah Sakeet Tehsil. Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0 00 hectares in villages Lalgarhi Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Hectare					
Etah	Etah	Etah Sakeet	Lalgarhi	874	0 0272
Total. .					0.0272

SCHEDULE-B
(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition

Notification of Declaration by Collector
[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9711 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0 0272 hectares of land in villages Lalgarhi Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is

required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector Etah

स० 138/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2 x 660मे०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम-मुख्तायलपुर में स्थित 0.2182 हेतु भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9719/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा-19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम मुख्तायलपुर की शून्य भूमि का विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापित कलेक्टर का निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	मुख्तायलपुर	41 अ 33 अ	0.2000 0.0182
					योग. .
					0.2182

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल	6
1	2	3	4	5		
					शून्य	

टिप्पणी - उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जयाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2x660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन एठा के एठा से मलावन रेल नेटवर्क' हेतु जनपद एठा परगना एठा सकीट व तहसील एठा ग्राम मुख्यायलपुर मे स्थित 02182 हेठा भूमि के लिये प्रकाशित 9719/अ0जिठम०आ0/आगरा दिनांक 09 06 2022 के क्रम मे मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है-

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी लघु कृषक की श्रेणी मे आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एठा के कार्यालय मे भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह0 (अस्पष्ट)
कलेक्टर एठा

No. 138/A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no 9719 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0 2182 hectares of land in the villages Muktayalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02 08 2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0 00 hectares in villages Muktayalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE-A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Etah	Etah	Etah Sakeet	Muktayalpur	41 अ	0.2000
				33 अ	0.0182
				Total. .	0.2182

SCHEDULE- B**(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition

Notification of Declaration by Collector**[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]**

By the order of declaration made under Government notification no 9719 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0 2182 hectares of land in villages Muktayalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Therma Power Project through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of Small farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector Etah.

स० 139/अ०जि०भ०आ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 X 660में०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क" हेतु जनपद एटा परगना एटा स्कीट व तहसील एटा ग्राम-नरहरा में स्थित 0.0052 हेंड भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9715/अ०जि०भ०आ०/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा स्कीट ग्राम नरहरा की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापिति कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित आर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
एटा	एटा	एटा सकीट	नरहरा	3	0 00028
				5 स	0 00023
				7	0 00065
				187	0 00186
				217	0 00016
				5	0 00202
				योग.	0.0052

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी — उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि�० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2X660मेओवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क' हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम—नरहरा में स्थित 0 0052 हेठो भूमि के लिये प्रकाशित 9715/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में भूमि आर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट)

कलेक्टर, एटा

No. 139/A.D.M.(L.A.)Agra—Whereas Preliminary notification no 9715 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0052 hectares of land in the villages Narhara Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Narhara Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Etah	Etah	Etah Sakeet	Narhara	3	0.00028
				5 स	0.00023
				7	0.00065
				187	0.00186
				217	0.00016
				5	0.00202
				Total..	0.0052

SCHEDULE-B

(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9715/ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0.0052 hectares of land in villages Narhara Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

*(Sd) ILLEGIBLE,
Collector, Etah*

स० 140/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा “2 x 660मेंवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क” हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम बाबरपुर मे स्थित 0.1680 हेक्टर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1, के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9714/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2, के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियो के परिपेक्ष्य में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम-बाबरपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापित कलेक्टर को निर्देशित करते है पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
एटा	एटा	एटा सकीट	बाबरपुर	41 स	हेक्टेयर 0.1680
				योग	0.1680

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-१९ की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा 2×660 मॉवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकोट व तहसील एटा ग्राम बाबरपुर में स्थित ० १६८० हेतु भूमि के लिये प्रकाशित ९७१४/३०३००५००/आगरा दिनांक ०९.०६.२०२२ के क्रम से मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है

परियोजना से प्रभावित भू-स्थानी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

५० (अस्पष्ट)

कलेक्टर, एटा

No. 140/A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no 9714.ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of ० १६८० hectares of land in the villages Babarpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for २x६६०MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of ० ०० hectares in villages Babarpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Etah	Etah	Etah Sakeet	Babarpur	41 स	0 1680
				Total..	0 1680

SCHEDULE-B

(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9714 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0 1680 hectares of land in villages Babarpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector Etah

स० 141/अ०जि०भ०३०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा “2 x 660 में०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा स्कीट व तहसील एटा ग्राम बरथरी में स्थित ० ०123 ह० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9718/अ०जि०भ०३०/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधिकों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपक्ष में धारा-19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम बरथरी की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2, के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापित कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
एटा	एटा	एटा सकीट	बरथरी	915/2	हेक्टेयर
					0 0123
				योग.	0.0123

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी : उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मेंवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम बरथरी में स्थित 0 0123 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित 9718/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है।

परियोजना से प्रभावित भू-स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

हेक्टेयर,

कलेक्टर, एटा

No. 141/A.D.M.(L.A.)Agra—Whereas Preliminary notification no 9718 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0 0123 hectares of land in the villages Barthari Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02 08 2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Barthari Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Hectare					
Etah	Etah	Etah Sakeet	Barthari	915/2	0 0123
Total. .					0.0123

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9718/ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0 0123 hectares of land in villages Barthari Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW Jawaharpur Thermal Power Project through Jawaharpur Vidyut

Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector Etah

स० 142/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2ग660म०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम कीलरमऊ में स्थित 00191 हेठो भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में अचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9721/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा का परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिषेक्ष्य में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम कीलरमऊ की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रमाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापि कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	कीलरमऊ	1093	0.0042
				1119	0.0006
				1120	0.0022
				1121	0.0023
				1096	0.0003
			983 क		0.0010
			984		0.0011
			985 क		0.0008
			986		0.0022
			988 क		0.0036
			929		0.0008
			योग		0.0191

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिंग के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2 x 660मेओवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क' हेतु जनपद एटा परगना एटा स्कीट व तहसील एटा ग्राम—कीलरमऊ में स्थित 00191 हेतु भूमि के लिये प्रकाशित 9721/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है—

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट)

कलेक्टर, एटा

No. 142 A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no. 9721 ADM (L.A) Agra Dated 09.06.2022 was issued under sub-section(1) of section 1. of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 00191 hectares of land in the villages Keelarmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Maawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 000 hectares in villages Keelarmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Etah	Etah	Etah Sakeet	Keelarmau	1093	0.0042
				1119	0.0006
				1120	0.0022
				1121	0.0023
				1096	0.0003
				983 क	0.0010
				984	0.0011
				985 क	0.0008
				986	0.0022
				988 क	0.0036
				929	0.0008
				Total .	0.0191

SCHEDULE- B
(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
				Nil	

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9721/ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 for 0.0191 hectares of land in villages Keelarmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector Etah.

स0 143/अ0जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा “2X660मे०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम उद्दनपुर रामनगर मे० स्थित 0.0585 हे० भूमि के सम्बन्ध मे० भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन मे० उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9709/अ0जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्रविधानों के अनुपालन मे० कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष मे० धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” मे० वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” मे० उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम उद्दनपुर रामनगर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्ब्यवस्थापन क्षेत्र के रूप मे० चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापि कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	उद्दनपुर रामनगर	224	0.0385
				243	0.0200
				योग.	0.0585

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारो के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप मे० चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी :—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय मे० देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा “2X660मे०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम उद्दनपुर रामनगर मे० स्थित 0.0585 हे० भूमि के लिये प्रकाशित 9709/अ0जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09.06.2022 के क्रम मे० मरे

द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है-

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उददेश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट)

कलेक्टर, एटा

No. 143/A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no 9709 ADM(LA) Agra Dated 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0 0585 hectares of land in the villages Uddanpur Ramnagar Pargana Etah Sakeet Tehsil. Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Uddanpur Ramnagar Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Uddanpur Ramnagar	224	0.0385
				243	0.0200
				Total. .	0.0585

SCHEDULE-B

(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
				Nil	

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition

Notification of Declaration by Collector
[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9709/ADM(LA) Agra Dated 09.06.2022 for 0.0585 hectares of land in villages Uddanpur Ramnagar Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Etah

स० 144/अ०जि०भ०अ०/आगरा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2X660में०वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम लोयाबादशाहपुर पीतमसिंह मे स्थित 0.4260 ह० भूमि के सम्बन्ध मे भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9716/अ०जि०भ०अ०/आगरा दिनाक 09.06.2022 को निगत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनाक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एटा का परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2), के प्राविधानों के अनुपालन मे कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनाक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तिया के परिपक्ष मे धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हे यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" मे वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" मे उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम लोयाबादशाहपुर पीतमसिंह की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप मे चिह्नित किया गया है

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापि कलेक्टर को निर्देशित करते हैं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ सलग्न है।

अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	लोयाबादशाहपुर पीतम सिंह	305	0.4260
					घोग. . 0.4260

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप मे चिह्नित मूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय मे देखा जा सकता है

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की घारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा '2X660मेओवाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा ग्राम लोयाबादशाहपुर पीतमसिंह मे स्थित 0.4260 हेक्टर भूमि के लिये प्रकाशित 9716/अ०जि०म०अ०/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम मे मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश सलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है

परियोजना से प्रभावित भू स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी मे आते है

उक्त भूमि का स्थल नवला कलेक्टर, एटा के कार्यालय मे भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है

ह० (अस्पष्ट),

कलेक्टर, एटा

No. 144 A.D.M.(L.A.)Agra Whereas Preliminary notification no 9716.ADM(LA) Agra Dated 09.06.2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.4260 hectares of land in the villages Loya Badshahpur Peetamsingh Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rai. Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Collector, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Loya Badshahpur Peetamsingh Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith

SCHEME-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Etah	Etah	Etah Sakeet	Loya Badshahpur Peetamsingh	305	0.4260
				Total.	0.4260

SCHEDULE- B**(Land Identified Settlement Area for Displaced Families)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector**[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]**

By the order of declaration made under Government notification no 9716/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.4260 hectares of land in villages **Loya Badshahpur Peetamsingh** Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rai. Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

Land affected by project comes under the category of marginal farmer

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(Sd) ILLEGIBLE,
Collector Etah



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आस्तिवन 23, 1944 शक संवत्)

भाग ३

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड के नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख नगर पचायत
खण्ड-ग निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ जिला पचायत

खण्ड-घ जिला पंचायत

कार्यालय, जिला पंचायत, कौशाम्बी

निम्नांकित उपविधि का प्रकाशन जन सामान्य को सूचनार्थ किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक महीने के अन्दर अपर मुख्य अधिकारी जिला पचायत कौशाम्बी के कार्यालय में सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के उपरान्त किसी सुझाव अथवा आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

मवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित करने की उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत कौशाम्बी ने ग्राम्य क्षेत्र जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र०० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उददेश्य से निम्न उपविधिया बनायी हैं यह उपविधि जिला पंचायत कौशाम्बी ने अपने प्रस्ताव सख्त्या ०१ दिनाक २४.१२.२०२१ हारा प्रस्तावित किया है, जो आयुक्त महोदय प्रयागराज मण्डल प्रयागराज के हारा अधिनियम की धारा 242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि किये जाने के उपरान्त राजकीय गज़ट पत्र (गज़ट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

१ अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र०० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 से है

२ ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में रिथत प्रत्येक नगर पंचायत नगर पालिका परिषद् छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या य०पी०एस० आई०डी०सी० के हारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम गाटा/खसरा सख्त्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गज़ट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

३ विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के द्वाइग डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना या उसमें सारबान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊँचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है भवन की ऊँचाई में मस्ती मशीनरुम, पानी की टकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-इनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसाई स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिये किया जाता है इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10-तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है जहां पर सामान्यत किसी भवन में चला फेरा जाता हो।

11-फ्लार एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12-भू आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13-ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हो तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग पार्क बाजार जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14-ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड भवन खण्ड मार्ग खुली जगह आने-जाने के बिन्दु पार्किंग व्यवस्था भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इग्नित करने वाला प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है।

अ अभियता अभियता जिला पचायत कौशाम्बी

ब अवर अभियता इस उपविधि में अवर अभियता का तात्पर्य उस अवर अभियता से है जिसको अभियंता जिला पचायत द्वारा भवन के नक्शां की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designated) किया गया हो।

16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पचायत कौशाम्बी से है।

17-अधिभाग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभाग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति व्यक्तियों का समूह कम्पनी ट्रस्ट पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19-रेन वाटर हार्डस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू गर्भ जल के स्तर को ऊचा उठाने से है।

20-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पचायत कौशाम्बी से है।

22-जिला पचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पचायत कौशाम्बी से है।

23-अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पचायत कौशाम्बी से है।

24-बहु मंजिली भवन (Multi Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25-मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हो तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हो।

26-भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा सरचना से है जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये एवं उसका प्रत्येक भाग याह मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद कुर्सी क्षेत्र दीवार फर्श छत चिमनी पानी की व्यवस्था स्थायी प्लैटफार्म बरान्डा बालकनी कार्नेस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके

अन्तर्गत टन्ट शामियाना तिरपाल आदि जोकि पूर्णत अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में समिलित नहीं होगे

27 आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन समिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हैं

28-व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन थोक या फुटकर बिक्री व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल पैट्रोल पम्प कन्फीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांतिक हो और उसी भवन में स्थित हो समिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो

29-सकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग समिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिंग जहरीली या खतरनाक क्षार तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वला भाप पैदा होती हो विस्फोटक जहरीले इरीटन्ट या कारोसिंग गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छाटे 2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो

30-भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी

31-पर्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बद या खुले स्थान से है जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में समिलित नहीं हैं का तात्पर्य वही होगा जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे

उपविधि

ये उपविधिया जिला पचायत कौशाम्बी के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है में किसी भी व्यक्ति ठक्करार कम्पनी फर्म या संस्था सहकारी समिति सोसाईटी राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय व्यावसायिक औद्योगिक भवन शिक्षण संस्थान फार्म हाउस ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों मार्केट धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार करना आवश्यक नहीं होगा

1 उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण परिवर्तन विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी

अ ये उपविधिया कच्चे मकानों एवं गाव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं दो मजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी

ब सफेदी व रग-रोशन के लिए

स प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

य पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए ।

र प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण

व मिटटी खोदने या मिटटी से गड्ढा भरना ।

(ख) प्रार्थना पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर

मुख्य अधिकारी जिला पचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाये प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा

1 स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा

लैं-आउट प्लान का पैमाना 1 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1 1000 होगा

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 100 होगा

स्थल के चारों तरफ की सीमाये उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जैसे विक्रय आलेख दाखिल खारिज खतौनी आलेख

2 प्रस्तावित भवन परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा ।

अ प्रत्येक मजिल के ढंके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

ब नक्शे पर पजीकृत वास्तुविद का पजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर

स नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर

द भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र

य भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय व्यवसायिक शिक्षण धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन

र स्थल का की-प्लान लैं-आउट प्लान फ्लॉर-प्लान एलिवेशन भवन की ऊँचाई संक्षन, स्ट्रक्चर विवरण ऐन हार्डिंग प्रणाली बेसमेंट लैडरस्केप प्लान वातानुकूलित प्लाट सीवेज जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण

ल नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक भू-खण्ड का खसरा ग्राम तहसील सहित का पूरा पता

ब नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल ग्राउड कवरेज हर तल का क्षेत्रफल बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण ।

3 बहु मजिली भवन (मल्टी स्टोरी) घार मजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितिया

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण परिवर्तन विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि

अ प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है

ब प्रस्तावित निर्माण धर्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धर्मिक भावनाएं आहत होती हो

स प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1 के एक आवास गृह में 45 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है

ख भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी

- ग- लिटल (Linte) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा यदि बेसमेट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 20 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है
- ड- बहु मजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/ मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा
- च- राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार युप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 60 मीटर से 160 मीटर की दूरी होगी भवन की 180 मीटर ऊँचाई तक 60 मीटर इसके पश्चात प्रत्येक 30 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 10 मीटर बढ़ाई जायेगी भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 90 मीटर होगी
- छ- बहु मजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 24 मीटर होगी।

2. निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है
- क- जेनरेटर कक्ष सुरक्षा मचान सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम टॉयलेट ब्लॉक झाईवर रूम विद्युत उप केन्द्र आदि ख- मस्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लाट।
- ग- ढके हुए पैदल पथ आदि
3. क- आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए ख- छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।
- ग- ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए
- घ- रसोइघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए
- ङ-संयुक्त सडास (TOILET) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए
- च- खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए
- छ- तीन मजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।
- 4- क- पार्क टोट-लोट्स (Tot-Lots) लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा ख- 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रट सेट बैक के योग का ढेढ़ गुना होगी
- ग- भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाइन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाइनर की होगी
5. स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा सवय की जायेगी जिला पदाधित का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।
- 6-बेसमेट में इलेक्ट्रिक ट्रास्फार्मर की स्थापना ज्वलनशील विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा

(इ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा

(व) विकसित जनपदों की सूची (I)

लखनऊ गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद मेरठ आगरा कानपुर नगर वाराणसी, मथुरा इलाहाबाद (प्रयागराज) बरेली सहारनपुर, अलीगढ़ गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली मुजफ्फरनगर एवं झौसी

(છ) ભૂ-આચ્છાદન એવં ફલોર એરિયા રેશિયો (FAR)

વિભિન્ન મંત્રનોં હેતુ ભૂ-આચ્છાદન એવં ફલોર એરિયા રેશિયો FAR) કે માનક નિમનાત્મ હોગે-

ક્રમાંક	મંત્રન એવં ભૂ-ઉપયોગ	ભૂ-આચ્છાદન પ્રતિશત	ફલોર એરિયા રેશિયો (FAR)	મંત્રન કી અધિકતમ કેંચાઇ સૂચી (I) કે અનુસાર જનપદો મેં (મીટર)	મંત્રન કી અધિકતમ કેંચાઇ અન્ય જનપદો મેં (મીટર)
1	2	3	4	5	6
1	(i) આવાસીય મંત્રન ભૂ-ખણ્ડ 500 વર્ગ મીટર તક	80	3.00	15	15
	(ii) આવાસીય મંત્રન ભૂ-ખણ્ડ 500-2000 વર્ગ મીટર તક	65	4.00	15	15
2	શુપ હાઉસિંગ યોજના, નિન બસેરા (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	ઔદ્યોગિક મંત્રન	60	1.00	18	12
4	વ્યાવસાયિક મંત્રન				
	(i) સુવિધા (Convenient) શૉપિં કેન્દ્ર શૉપિં માલ્સ, વ્યાવસાયિક કેન્દ્ર હોટલ	40	2.50	30	21
	(ii) બૈંક, સિનેમા મલ્ટીપ્લેક્સ	40	1.50	24	18
	(iii) વેશરહાઉસ, ગોડામ	60	1.50	18	15
	(iv) દુકાને વ માર્કેટ	60	1.50	15	10
5	સંસ્થાગત એવં શૈક્ષણિક મંત્રન				
	(i) સભી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાન વિશ્વવિદ્યાલય, અનુસંધાન એવં પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન ડિફ્રી કોલેજ આદિ	50	1.50	24	15
	(ii) હાયર સેક્યુલરી, પ્રાઇમરી, નર્સરી સ્કૂલ ક્રેચ મેટર આદિ	50	1.50	24	15
	(iii) હોસ્પિટલ ડિસ્પેન્સરી, ચિકિત્સાલય, લૈબ નર્સિંગ હોસ્પિટાલ આદિ	75	2.50	24	15
6	ધર્માથ અથવા જનહિતાર્થ મંત્રન	50	1.20	15	10
	(i) સામુદાયિક કેન્દ્ર કલાબ, બારાત ઘર જિમખાના, અભિનિષ્ઠાન કેન્દ્ર, ડાકઘર, પુલિસ સ્ટેશન	30	1.50	15	10
	(ii) ધર્મશાલા, લોાંજ, અતિશિંગ્રૂહ હોસ્ટલ	40	2.50	15	10
	(iii) ધર્મકટ્ટા, પેટ્રોલ પાથ્ય, ગેસ ગોડામ, શીલ ગૃહ	40	0.50	10	6
7	કાર્યાલય મંત્રન				
	સરકારી, અર્થસરકારી કોર્પોરેટ એવં અન્ય કાર્યાલય મંત્રન	40	2.00	30	15
8	ક્રીડા એવં મનોરજન કોમ્પ્લેક્સ શૂટિંગ રેઝ સ્ટ્રાન્ડાજિક એવં સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર	20	0.40	15	10
9	નર્સરી	10	0.50	6	6
10	બસ સ્ટેશન, બમાંડિપો, કાર્યશાલા	30	2.00	15	12
11	ફાર્મ હાઉસ	10	0.5	10	6
12	ફેરી ફાર્મ	10	0.15	10	6
13	મુગા, સૂઅર, બકરી ફાર્મ	20	0.30	6	6
14	એં ટીંઓ એમ્ઝો	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (set back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साइड (Side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैंड स्केपिंग (landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्गमीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सास्कृतिक केंद्र	एक ECU प्रति 50 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का

(ज) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

- तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।
- अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी० राईजर अधिकतम 19 सेमी० एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की सख्त्या 16 तक सीमित होगी।
- अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।
- घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।
- उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मदारी भवन स्वामी की होगी।

(v) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग 4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित सिप्रिलर पद्धति फर्स्ट एड हाज रील्स स्वचालित अग्नि संसुचन और चेतावनी पद्धति सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षेत्रिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एड मीडियम बोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई बोल्टेज लाईन 33000 बोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एकस्त्रा हाई बोल्टेज लाईन अतिरिक्त 33000 बोल्टेज पर	3.7+(0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 बोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 बोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

(क) मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु मवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी

(ख) जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होगे तथा भू तल पर ही लगाये जायेंगे

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए

(घ) जहाँ अपेक्षित हो वहा टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा

(ङ) सेवा ऑपरेटर कपनी और मवन स्वामी को सयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस पास के मवन एवं जान माल को किसी भी प्रकार कि क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कपनी और मवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैक्स रेडियो विकिरण वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (I) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पचायत में जमा कराने होंगे यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे

(ज) शैक्षणिक संस्था हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय वस्ती अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

क. आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर ₹०.50 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर ₹०.25 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर ₹ 100 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर ₹ 50 प्रति वर्ग मीटर होगी

ग (i) भूमि की प्लाटिंग भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बाँटना

(ii) भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क उद्यान बनाना फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग-भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कटनर इंधन आर०सी०सी० पाईप आदि

(iv, किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग-(i) से (iv) तक सूची (I) के अनुसार जनपदों में ₹ 20 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर ₹ 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी

घ पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुन निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरे नये भवन की दरों के समान होंगी

इ-स्वीकृत भवन के नक्शे में सशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरे नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी

च बेसमेट स्टिल्ट पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी

छ यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होगी एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात नवीनीकरण की दरे मूल दरों की 50% होंगी

ज उपविधियों के अनुसार, जिला पचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने किसी भूमि पर व्यवसाय करने स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरात पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियंत्रित होगी

झ सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें ₹ 20 प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर होंगी ये दरे सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी

ए सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्डी बाल स्वीकृति की दर ₹ 10 प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में ₹ 5 प्रति मीटर होगी

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1 स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वाभित्य के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी

2- ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ सलग्नको को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठाकित कर देगा।

3- कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पचायत को प्रस्तुत कर देगा कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4- कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियता जिला पचायत को पृष्ठाकित कर देगा।

5-अभियता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निर्दिशित (Designated) अवर अभियता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6-अवर अभियता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियता जिला पचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7- अवर अभियता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमजिली भवन व्यवसायिक भवन सकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8-अभियता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरात सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा परीयोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियता से एक अतिरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पचायत में जमा करनी होगी इसके उपरान्त ही नक्शों के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी प्रतिबध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक माग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9- जिला पचायत के अभियता द्वारा परियोजना की सम्भाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenience) साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा आवश्यकता समझने पर नक्शों में सशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्दिशित किया जायेगा।

10- अभियता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी अवर अभियता से आगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ सलग्न करना होगा।

11- अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का माग-पत्र जारी करेंगे जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12-आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13- उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियता के सयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियता द्वारा सयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14- यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के सङ्गान में लिखित रूप से लाया जायेगा यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद-उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष जिला पंचायत को संदर्भित

किया जायेगा जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभ्यपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1- भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा सरक्षित ऐतिहासिक स्मारक इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 15 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मनिलों एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2- भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

3- भवन के भू-तल पर स्टिल पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग बेसमेट वाहन पार्किंग भडारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4- निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी० की परिधि में 30 मी० से ऊचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

5- उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6- उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7- मल्टी लेवल पार्किंग में सरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेट अनुमत्य होगे।

8- इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनाक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9- इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरात यदि यह सज्जान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है किया गया निर्माण घ्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियता जिला पचायत की सरस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे परियोजना का डिजाइन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति कम्पनी फर्म या संस्था राजकीय विभाग अथवा टेकंदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पचायत एवं जिला पचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पचायत कौशाम्बी यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो अकन रु0 1000 तक होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का मुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो कि तीन माह तक हो सकेगा

विजय विश्वास पन्त

मण्डलायुक्त

प्रयागराज



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आस्थिवन 23, 1944 शक संवत्)

भाग ४

सरकारी कागज-पत्र दबाई हुई रुई की गाढ़ी का विवरण-पत्र, जन्म मरण के आकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और क्रह्तु सम्बन्धी रिपोर्ट बाजार भाव सूचना, विज्ञापन इत्यादि
कार्यालय, नगर पंचायत छुटमलपुर, जनपद सहारनपुर

विविध उपनियमावली

०१ अक्टूबर 2022 ई०

स० १६५ / न०प०छु० / २०२२-२३ नगर पंचायत छुटमलपुर जनपद सहारनपुर में नगर पालिका अधिनियम १९१६ की धारा २९८ एवं उसमें दी गई विविध उप धाराओं तथा शासन द्वारा समय २ पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देश के क्रम में—

१ वाणिज्य नियन्त्रण एवं लाइसेंस शुल्क उप नियमावली २ भवन मानवित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली ३ बिल एवं विज्ञापन शुल्क उपनियमावलियों को बनाया गया जिसको प्रशासक नगर पंचायत छुटमलपुर/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय)/अपर जिलाधिकारी (प्र०) जनपद सहारनपुर द्वारा दिनाक २२ अगस्त २०२२ द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया उपविधि पर दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने हेतु उपनियमावलियों को नियमानुसार समाचार-पत्रों १ दैनिक जागरण २ अमर उजाला में दिनाक २४ अगस्त २०२२ से दिनाक २३ सितम्बर २०२२ तक समाचार पत्रों के माध्यम से ३० दिन के अन्दर आपत्ति आमत्रित की गयी है किन्तु ३० दिन के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई

अत नगर पालिका अधिनियम १९१६ की धारा २९८(१) के अन्तर्गत उपविधि को गज़ट के आगामी अक मे प्रकाशित करने हेतु सेवा मे भेजा जा रहा है उपविधि राजकीय-पत्र (गज़ट) में प्रकाशन के दिनाक से प्रभावी माना जायेगा।

परिमाषा—विषय या प्रसग मे कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में—

१ उपविधि का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत छुटमलपुर जनपद सहारनपुर द्वारा बनाई गई उपविधि से है

२ अधिनियम से तात्पर्य उपर्योग नगरपालिका अधिनियम १९१६ से है।

३—नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर से है।

4—अधिसूचना से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

5—विहित अधिकारी का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।

6—कर/शुल्क का तात्पर्य विभिन्न उपनियमावलियाँ में वर्णित विविध मदों पर लगाये गये कर/शुल्क से है।

7—नगर पचायत क्षेत्र से तात्पर्य नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।

8—नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर से तात्पर्य सविधान के अनुच्छेद 243-घ के खण्ड-1 के उपखण्ड (क) के अधीन व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के अधीन गठित नगर पचायत से है।

9—सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसी जगह से है जो किसी की निजी सम्पत्ति न हो और आम जनता के उपयोग-उपभोग के लिये खुला हो आहे ऐसी जगह नगर पचायत में निहित हो अथवा नहीं।

10—सकमिति क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो नगर पचायत के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन वर्तमान में निकाय के आबादी क्षेत्र में प्रसार होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाये जैसे-सड़क, नाला-नाली का निर्माण साफ-सफाई पेय-जल प्रकाश व्यवस्था नगर पचायत छुटमलपुर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है पर भी यह नियमावली लागू समझी जायेगी।

11—अध्यक्ष नगर पचायत से तात्पर्य निकाय छुटमलपुर की जनता द्वारा चुने गये अध्यक्ष से है।

12—अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पचायत छुटमलपुर में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

13—प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निकाय के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से है।

14—प्रशासक से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर के लिये प्रशासक के पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी से है।

15—लेखाकार/लेखा लिपिक से तात्पर्य शासन के आदेश के अनुक्रम में निकाय में नियुक्त किये गये लेखाकार/लेखालिपिक से है।

16—कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से तात्पर्य नगर पचायत छुटमलपुर में इन पदों पर कार्यरत समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से है।

17—अन्य बातों के रहते हुए अगर किसी शब्द की परिभाषा उपविधियों में प्रसारित नहीं है तब उसका अर्थ नगरपालिका अधिनियम में दी गई परिभाषा से लिया जायेगा।

18—नगर पचायत सेवक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पचायत से वेतन प्राप्त करता है और उसकी सेवा में हो।

19—ठेकेदार से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने सीलबन्द निविदा देकर या सरेआम बोली लगाकर ठंके को वसूलने का नगर पचायत से अधिकार प्राप्त किया हो।

1—वाणिज्य नियंत्रण एव लाइसेन्स शुल्क उपनियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(1) नगर पचायत छुटमलपुर, सहारनपुर की वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेन्स उपनियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

(3) इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एव आदेश निष्पादिती माने जायेगे।

नियम व शर्ते-

क्र०स०	विवरण	प्रस्तावित दरें
1	2	3
		रु०
1	होटल लाजिंग तथा ग्रेट हाऊस 10 शैया	1000.00 प्रतिवर्ष
2	तीन सितारा होटल	9000.00
3	पाँच सितारा होटल	12000.00
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (10 बेड तक)	1000.00 प्रतिवर्ष
5	नर्सिंग होम (10 बेड से 20 बेड तक)	2000.00 प्रतिवर्ष
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2000.00 प्रतिवर्ष
7	प्रसूति गृह (20 बेड से 50 बेड तक)	3000.00 प्रतिवर्ष
8	प्राइवेट अस्पताल	2000.00 प्रतिवर्ष
9	पैथालॉजी सेन्टर	1000.00 प्रतिवर्ष
10	एक्सरै/अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक	1000.00 प्रतिवर्ष
11	डेन्टल क्लीनिक	2000.00 प्रतिवर्ष
12	प्राइवेट क्लीनिक	1000.00 प्रतिवर्ष
	परिवहन	
13	आटो रिक्शा (2सीटर)	360.00 प्रतिवर्ष
14	आटो रिक्शा (7सीटर)	720.00 प्रतिवर्ष
15	आटो रिक्शा (4सीटर)	600.00 प्रतिवर्ष
16	मिनी बस	1500.00 प्रतिवर्ष
17	बस	2500.00 प्रतिवर्ष
18	तागा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	150.00
20	रिक्शा निजी चालित	50.00
21	ठेला / ठेली	100.00
22	हथ ठेला	50.00
23	बैल गाड़ी/मैसा गाड़ी	150.00
24	रेहडा मोटर साईकिल	500.00
25	ट्रॉली	150.00
	अन्य व्यवसाय	
26	फाइनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड	4000.00 प्रतिवर्ष
27	इन्सोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	4000.00
28	पशुवध (स्लाटर हाऊस)	10.00
29	हड्डी, खाल, सीग, गोदाम	1000.00
30	बार बियर	6000.00
31	आईस फॉट्री	200.00
32	लघु उद्योग	500.00
	दुकान	
33	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5000.00 प्रतिवर्ष
34	देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)	6000.00 प्रतिवर्ष
35	अंग्रेजी शराब / बियर की दुकान (प्रति दुकान)	12000.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
	पशुपालन	रु०
36	पालतू पशु प्रति	10.00
37	काजी हाउस मे बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00 प्रति पशु
38	काजी हाउस मे बन्द जानवर प्रति खुराकी छाटे जानवर बकरी आदि	10.00 प्रतिदिन
39	प्रति खुराकी बडे जानवर (गाय, भैंस, घोड़ा आदि)	25.00 प्रतिदिन

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर यह निर्देश देती है की उपरोक्त उपविधि में दिये उपनियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर मु० 1000.00 (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड दिया जायेगा जो किसी भी दशा मे रुपये 2500.00 (दो हजार पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा) यदि अपराध निरन्तर करता मिलता है तो दोष सिद्ध होने के दिनांक से अंकन रुपये 25.00 प्रतिदिन की दर से जुमाना दण्डनीय होगा।

2—भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली

सक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(1) यह उपनियमावली नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर की भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 मे दिये गये प्राविधान तथा समय समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

(3) इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध मे पूर्व मे जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेगे।

(4) भवन का तात्पर्य किसी मकान उपग्रह अस्तवज्ज झादक (शेड), झोपड़ी या अन्य बाड़ा या ढाँचे से है, याहे वह पक्की ईंट लकड़ी मिटटी धातु या चाहे किसी अन्य पदार्थ से बना हो याहे उसका उपयोग मनुष्य के रहने के लिये अथवा किसी अन्य कार्य के लिये किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, मकान की कुर्सी जीना देहली दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से सनलग्न न हो की चारदीवारी से भिन्न किसी आहत की दीवार समिलित है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य काई परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।

(5) "नक्शा नवीस/मानचित्रकार/ड्रॉफ्टमैन" का अभिप्राय नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्र/नक्शा से है।

(6) "व्यवसायिक निर्माण से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार उद्याग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हो।

(7) 'जनोपयोगी सेवा क निर्माण' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा जिसमे वृद्धा आश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

(8) शासकीय सम्पत्ति से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर की सीमा मे किया गया हो जिसमें अस्पताल थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय आदि के भवन से है।

(9) निवास गृह से तात्पर्य ऐसे भवनों से है जिनका उपयोग तीर्थ यात्रियों को ठहराने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिए निर्मित हो से है।

नियम व शर्तें—(1) आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 1 प्रथम तल 100 वर्ग मीटर तक 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 101-200 वर्ग मीटर तक 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 200 वर्ग मीटर से ऊपर प्रत्येक वर्ग मीटर पर 15 रुपये शुल्क देय होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

2 व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों व्यापारिक, गोदाम बैंक सिनमा, थियेटर स्केटिंग हाल बारात घर नर्सिंग होम व्यवसायिक काम्प्लैक्स क्लब एवं शारूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के लिए मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल की आच्छादित क्षेत्रफल पर प्रथम 100 वर्ग मीटर पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर 101 वर्ग मीटर या इससे अधिक पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लागू होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

3 औद्योगिक भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय शुल्क होगा।

4- ईक्षिक धार्मिक तथा धर्मार्थ एवं जनोपयोगी सेवा के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा बैस मेन्ट 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

(क) भू-तल सहित तीन मजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त भवन/मजिल तल अथवा बहुमजिल भवन भूकम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेग

(ख) निर्मित किये जाने वाले भवनों में 101-200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय जल सचयन हेतु साकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा 201-300 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत करकरीट रहित कच्चा छोड़ना होगा तथा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करने के लिये छतवर्षा जल सचयन प्रणाली/रुफ रैन वाटर हार्डिंग प्रणाली सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा

(ग) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्धन या नियन्त्रण में काई बाजार स्कूल थियेटर सिनेमा सावजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री) आदि हो उनमे संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था तथा दैनिक सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा

(घ) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिये अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित हो उनके निर्माण पूर्व होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा प्रस्तुत करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतं निरस्त समझा जायेगा।

(ज) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारा एवं गिरजा घर आदि से 200 वर्ग मीटर अर्धव्यास में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी

(च) उपर्युक्त धार्मिक स्थल निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी

5- स्वीकृति की अवधि

(क) पुनः वैधीकरण/स्वीकृत उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार एक बार केवल छ घं माह के लिये होगा, जिसके लिये प्रथम स्वीकृति शुल्क की 1/2 भाग धनराशि देय होगी इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण/स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा पुन नोटिस दिया जायेगा

(ख) यदि भवन स्वामी उक्त नियम 5(क) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व स्वीकृति को पुन वैध नहीं करता है तो अवधि दिनाक से तीन माह तक पुन वैधीकरण शुल्क के साथ रुपये 50 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तभी आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा इसके उपरान्त पुन वैधीकरण शुल्क सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा

(ग) भवन मानचित्र स्वीकृति की अवधि के दिनाक से छ घं माह की अवधि मे ही पुन वैधीकरण प्रभावी होगा

6- नगर पंचायत छुटमलपुर के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के सशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा

7- प्रत्येक प्रकार की चार दीवारी के लिये प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिये रुपये 100 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर या उसके माग पर रुपये 50 की दर से शुल्क देय होगा

8- संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 121 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों एवं परिसीमा के अधीन जो विहित की जायेगी किसी भवन मार्ग या नाले के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेंगी

9- उपरोक्त उपनियम/ भवन निर्माण के सम्बन्ध मे संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916 मे शासन द्वारा यदि कोई सशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा सशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम मे यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा

10- नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत छुटमलपुर के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा

11 मानचित्रकार/नक्शा नवीस के सम्बन्ध मे-

(क) नगर पंचायत द्वारा एक मानचित्रकार/नक्शा नवीस प्रत्येक वर्ष मानचित्र निर्माण हेतु रखा जायेगा मानचित्र का लाइसेन्स प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पूर्व माह फरवरी या मार्च मे आगामी वर्ष के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा

(ख) मानचित्रकार के लाइसेन्स स्वीकृति होने के नियम व शर्तें नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ग) प्रत्येक मानचित्र के आवेदन का शुल्क 100 वर्ग मीटर तक 500 रुपये प्रति मानचित्र तथा 100 वर्ग मीटर से अधिक 800 रुपये प्रति मानचित्र पर देय होगा जिसका मुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जायेगा

और શુલ્ક પ્રાપ્તિ કી રસીદ માનવિત્રકાર દ્વારા આવેદન કર્તા કી ઉપલબ્ધ કરાઈ જાયેગી જિસકી સૂચના માનવિત્રકાર નગર પચાયત કાર્યાલય કો દેગા

(ઘ) માનવિત્રકાર કા લાઇસેન્સ શુલ્ક 5000 રૂપયે વાર્ષિક હોગા

(ડ) નિકાય બોર્ડ દ્વારા 2 તિહાઈ બહુમત સે અથવા અધિશાસી અધિકારી દ્વારા જિલાધિકારી મહોદય/પ્રભારી અધિકારી સ્થાનીય નિકાય સ્વીકૃતિ પ્રાપ્ત કર માનવિત્ર બનાને કે શુલ્ક એવ માનવિત્રકાર કે લાઇસેન્સ શુલ્ક મેં વૃદ્ધિ કી જા સકતી હૈ લેકિન ઇન શુલ્કો મેં કિસી ભી સ્થિતિ મેં કટૌતી/કમી નહી કી જા સકતી હૈ

12- વ્યવસાયિક ભવનો કો અપને ભવન મે પાર્કિંગ કી વ્યવસ્થા સ્વય કરની હોગી

13- નગર પચાયત કી સીમા મે કિસી ભી આવાસીય/વ્યવસાયિક કાલોની કા નિર્માણ બિના નગર પચાયત કી સ્વીકૃતિ કે નહી હોગા તથા પ્રત્યેક કાલોની કે માનવિત્ર કી સ્વીકૃતિ કે લિયે કુલ ભૂમિ કા 2 રૂપયે પ્રતી વર્ગમીટર કી દર સે વિકાસ શુલ્ક દેય હોગા વ્યવસાયિક આવેદન માનવિત્ર શુલ્ક 1000 ર૦ હોગા

(ક) કાલોની કી સડક કમ સે કમ ૩ મીટર ચૌડી હોગી તથા મુખ્ય સડક સે એપ્રોચ રોડ કમ સે કમ ૬ મીટર ચૌડી હોગી।

(ચ) કાલોની મે નાલી પાની કી નિકાસી આદિ કી વ્યવસ્થા કાલોની સ્વીકૃત કરાને વાલે કો કરની હોગી

(ગ) કાલોની કી સડક પલકી કરને કી જિમ્મેદારી ભી કાલોની સ્વીકૃત કરાને વાલે કી હોગી

(ઘ) કાલોની મે પેડો આદિ કી વ્યવસ્થા ભી કાલોની સ્વીકૃત કરાને વાલે કી હોગી

(ડ) કાલોની મે પાર્ક આદિ કા નિર્માણ કરના હોગા

(ચ) યથા સમ્બંધ સડક સમકોણ પર મિલાઈ જાયેગી

(છ) કાલોની મે જલ પૂર્તિ કે લિયે પાઈપ લાઇન વ બિજલી કી વ્યવસ્થા ભી કાલોની સ્વીકૃત કરાને વાલે કો કરની હોગી

(જ) કાલોની સ્વીકૃત કરાને વાલે કો કાલોની કા પૂર્ણ નિર્માણ કરને કે પશ્ચાત્ પૂર્ણતયા કા પ્રમાણ પત્ર નગર પંચાયત સે પ્રાપ્ત કરના અનિવાર્ય હોગા તથા ઇસકે પશ્ચાત્ ઉક્ત કાલોની નગર પંચાયત કે પ્રબન્ધન મે જાયેગી ઔર કાલોની મે ગૃહ કર/જલ કર આદિ દય પ્રાપ્ત કરને કો અધિકાર નગર પંચાયત કા હોગા, તથા કાલોની મે વિભિન્ન સુવિધાઓ એવ ઉસકે રખ રખાવ કા ઉત્તરદાયિત્વ નગર પંચાયત કી હોગી

(ઝ) જહો પર નિર્માણ સમ્બંધી નિયમ સ્પષ્ટ નહી, વહો પર નૈશનલ બિલ્ડિંગ કોડ (એન૦બી૦સી૦) કે પ્રાવિધાન લાગુ હોંગ।

14- કિસી ભી માનવિત્ર કી સ્વીકૃતિ સે પૂર્વ ભૂમિ કે સ્વામિત્વ સમ્બંધી અમિલેખ એવ શપથપત્ર દિયા જાના અનિવાર્ય હોગા

15- માનવિત્ર સ્વીકૃતિ હોને કે પશ્ચાત્ યદિ ભૂમિ કે સ્વામિત્વ કિસી અન્ય વ્યક્તિ/સરસ્થા/સાર્વજનિક પાયી જાતી હૈ તો સ્વીકૃત માનવિત્ર સ્વત નિરસ્ત સમજા જાયેગા

16- ભવન નિર્માણ કે સમ્બંધ મે નગર પાલિકા અધિનિયમ મે દિયે પ્રાવિધાન એવ સમય સમય પર જારી કિયે ગયે શાસનાદેશ ઇસ ઉપનિયમાદળી પર પ્રભાવી હોગોં।

17- ભવન નિર્માણ માનવિત્ર સ્વીકૃતિ કે ઉપરાન્ત ભવન નિર્માણ કરતે સમય નગર પંચાયત કાર્યાલય દ્વારા સમય સમય પર ઉસકા નિરીક્ષણ કરાયા જાના અનિવાર્ય હોગા ઔર નિરીક્ષણ કે ઉપરાન્ત નગર પંચાયત કાર્યાલય દ્વારા દિયે ગયે નિર્દેશો કા પાલન કરના ભી અનિવાર્ય હોગા

18- કાઈ ભી વ્યક્તિ યદિ અપને મકાન કે સામને આગે આન કે લિયે ગલી/સડક કી નાલી વ નાલા છાપના ચાહેગા ઉસકી ભી સ્વીકૃતિ પ્રાપ્ત કરની હોગી

19- ભવન સમ્બંધી પત્રાદળી 5 વર્ષ તક રખી જાયેગી। સમય વ્યતીત હોને પર નષ્ટ કર દી જાયેગી

20- માનવિત્ર સ્વીકૃતિ કે ઉપરાન્ત ભવન નિર્માણ પૂર્ણ હોને પર સ્વામી દ્વારા નગર પંચાયત કાર્યાલય સે ભવન નિર્માણ પૂર્ણ સમ્બંધી પ્રમાણ પત્ર પ્રાપ્ત કરના અનિવાર્ય હોગા।

21- બોર્ડ અપને 2 તિહાઈ સદસ્યો કી સ્વીકૃતિ અથવા અધિશાસી અધિકારી/જિલાધિકારી મહોદય/પ્રભારી અધિકારી સ્થાનીય નિકાય કી સ્વીકૃતિ સે ઉપનિયમાદળી સે કિસી ભી ધારા મેં પરિવર્તિત કર સકતા હૈ યા કોઈ નઈ ધારા જોડ સકતા હૈ જો ઉપનિયમાદળી પર પ્રભાવી સમજી જાયેગી। લેકિન ઉપનિયમાદળી મેં વર્ણિત કિસી શુલ્ક મેં કોઈ કમી નહી કી જા સકતી હૈ

दण्ड

अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण का अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटाने का पूर्ण अधिकार नगर पचायत को प्राप्त होगा लेकिन प्रतिबन्ध यह कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नवीस से बनाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये नगर पचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पचायत ऐसे मानचित्र को समझौता शुल्क 500.00 रुपये से लेकर नियमित कर सकेगा लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क 1000.00 रुपये लिया जायेगा

3—बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली

सक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(1) यह उपनियम नगर पचायत छुटमलपुर सहारनपुर बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली कहलायेगी जो नगर पचायत छुटमलपुर के अधिसूची क्षेत्र एवं स्क्रमित क्षेत्र में राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी

2—नगर पचायत बोर्ड के द्वारा दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की सहमति से इस नियमावली के नियम व शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है जो नियमावली पर प्रभावी होगा लेकिन नियमावली के प्रभाव क्षेत्र में कमी करने एवं शुल्क में कमी करने का कोई भी स्वीकृत प्रस्ताव/सहमति नियमावली पर प्रभावी नहीं होगा।

3—नियमावली के नियम व शर्तों को कियान्वयित कराने का दायित्व नगर पचायत कार्यालय पर होगा

4—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 में दिये प्रावधान तथा समय समय पर जारी किये गये शासनादेश इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

5—इस नियमावली के लागू होने के बाद इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नियम व शर्तें—(1) नगर पचायत की सीमा के अन्दर अथवा सक्रिय क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी कम्पनी/फर्म अपने विज्ञापन के द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने हतु सार्वजनिक स्थानों पर ग्लोसाईन/साईन बोर्ड वाल पेन्टिंग बैनर कटाउट विज्ञापन पर बोर्ड पोस्टर, हैण्ड बिल लगायेंगा उसे नगर पचायत से या नगर पचायत द्वारा नामित ठेकेदार से अनुमति लेकर ही लगाना होगा और उसका मुगलान नगर पचायत को सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित शुल्क अदा कराना होगा।

2—विज्ञापनदाता विज्ञापन का प्रचार प्रसार ऐसे स्थानों का करेगे ताकि कम्पनी के प्रचार प्रसार से मर्ज स्थान ऐतिहासिक रथल की सूचना पर या अन्य किसी कम्पनी के प्रचार प्रसार हतु लगाये गये धारा (21) में प्रकाशित ग्लोसाईन आदि का विलुप्तिकरण न हो।

3—विज्ञापनदाता अपने आवेदन में एक सप्ताह पूर्व विज्ञापन का साइज प्रकार आकार एवं समय सहित देगा तथा उपविधि में वर्णित शुल्क जमा करेगा।

4—विज्ञापन की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता आवेदन करके विज्ञापन अवधि बढ़ायेगा यदि 30 दिन के अन्दर विज्ञापनदाता ऐसा नहीं करता है जो उपनियम की धारा 2 में प्रकाशित ग्लोसाईन को नगर पचायत या नगर पचायत द्वारा नामित ठेकेदार जब्त कर लेगा।

5—ग्लोसाईन बोर्ड आदि केवल सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर ही लगाये जायेंगे भल ही स्थान नगर पचायत की सीमा के अन्दर किसी भी अन्य विभाग के हो।

6—नगर पचायत प्रत्येक वर्ष के फरवरी मार्च के माह में विज्ञापन शुल्क वसूली हतु एक वर्ष के लिए ठेका उठायेंगी और ठेका सीलबन्द निविदा/कुटेशन पर उठाया जायेगा।

7—ठेका प्राप्तकर्ता ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा ठेके का समस्त धन एक मुश्त स्वीकृति की दिनांक के सात दिन के भीतर जमा करना होगा।

8—विज्ञापन शुल्क सरह (1) दुकानों के नाम साथ साथ या स्वतन्त्र रूप से अन्य किसी चीज का ग्लोसाईन/साईनबोर्ड लगाकर लिये जा रहे विज्ञापन के रु0.50 प्रति फिट प्रतिवर्ष की दर से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी।

(2) वाल पेन्टिंग रु0.300 प्रति वर्ग फिट वार्षिक

(3) बैनर 20 वर्ग फिट रु0.10.00 प्रतिदिन

(4) साईनबोर्ड/ग्लोसाईन बोर्ड (केवल कम्पनीयों के लिए) रु0.50.00 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष।

(5) कटाउट विज्ञापन एक नगर रु0.30.00 प्रति वर्ष

(6) बोर्ड पोस्टर रु0.400.00 प्रति सैकड़ा प्रति बार

(7) पोस्टर हैंड बिल रु0.200.00

9—शुल्क मुक्त सूची (1) दुकानों के सूचक राजकीय एवं शासकीय तथा राष्ट्रीय पर्याएं पर लगाये गये विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन शुल्क से मुक्त होंगे।

दण्ड

दण्ड उपविधि का उल्लंघन उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रु०-1000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो। रु० 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखा पर कर नियमावली

नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर आरोपित करने तथा उसकी वसूली करने के लिये नगर पंचायत छुटमलपुर द्वारा बनाये गये उपनियम का पाण्डूलेख—

१—संक्षिप्त नाम—(क) यह उपनियम नगर पंचायत छुटमलपुर जिला सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाने एवं वसूल करने सम्बन्धित उपनियम कहलायेगा।

(ख) यह उपनियम उत्तर प्रदेश राजकीय गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(ग) यह उपनियम नगर पंचायत छुटमलपुर जिला सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के सभी लेखों पर प्रयुक्त होगा।

२—कर का दायित्व—किसी विपरीत अनुबन्ध की दशा में देय कर को देने का दायित्व मारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 29 में वर्णित 'ड्यूटी' अदा करने वाले व्यक्ति का होगा।

३—कोई भी व्यक्ति जो नगर पंचायत छुटमलपुर, जिला सहारनपुर की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड वसीयतनामा, लिखनामा, कय विक्रय अथवा रहनामा द्वारा करायेगा उस पर उपनियम प्रभावी होगा।

४—सभी हस्तान्तरण की जाने वाली अचल सम्पत्ति के कुल मूल्य पर अथवा भोग बन्धक यूसुपुब्बेचअरी मार्गों की दशा में लिखित दस्तावेज प्रतिशत धनराशि पर यह कर 2 प्रतिशत की दर से नगर पंचायत छुटमलपुर, जिला सहारनपुर को देय होगा।

५—अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अवसर पर सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों या जैसी भी स्थिति हो के नगर पंचायत छुटमलपुर के लिये अचल सम्पत्ति मूल्य/स्टाम्प का शुल्क 2 प्रतिशत सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में जमा कराया जायेगा। 01 प्रतिशत रसीद के साथ ही साथ अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा निर्गत जमा धनराशि के सम्बन्धित प्रमाण-पत्र क्रेता को अपने अभिलेख के साथ कार्यालय को देने होंगे।

६—सम्बन्धित निवन्धन अधिकारी अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित दस्तावेज के पंजीयन के समय नगर पंचायत छुटमलपुर के लिये 02 प्रतिशत शुल्क जमा करायेंगे। प्रमाण-पत्र इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 27 की उपधारा के अनुपालन को देखेंगे और उक्त रसीद तथा प्रमाण-पत्र दस्तावेज के साथ संलग्न न होने पर हस्तान्तरण/पंजीयन स्वीकार नहीं करेंगे तथा इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 64 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की लिये उसे जिले के कलेक्टर के पास भेजेंगे।

(ख) जब यह सन्देह उत्पन्न हो की किसी भूमि अथवा भवन का मालिक कौन है ऐसी दशा में अधिशासी अधिकारी निश्चय करेगा कि किस हैसियत मालिक नाम दर्ज किया जाये। और अधिशासी अधिकारी का निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक किसी न्यायालय के द्वारा निर्णीत न किया गया हो।

७—(क) यदि किसी भूमि अथवा भवन जिस पर कर लगाया गया हो उसके स्वामी अपनी मिलकियत किसी दूसरे को हस्तान्तरित करेंगे तो आवश्यक होगा कि रजिस्ट्री होने अथवा कब्जा दिये जाने के तीन मास के भीतर जो व्यक्ति सम्पत्ति हस्तान्तरित करें अथवा हस्तान्तरित की जाये वे नगर पंचायत को लिखित सूचना देकर इन्द्राज करा लें।

(ख) ऐसी भूमि और भवन जिस पर कर देय हो उसके मालिक की मृत्यु पर मालिक के उत्तराधिकारी द्वारा तीन मास के भीतर इस प्रकार प्रार्थना-पत्र देकर नाम दर्ज कराया जायेगा। किन्तु केवल नाम परिवर्तन होने की कार्यवाही में विलम्ब के कारण वसूली स्थगित न की जायेगी।

८—(क) पहले नियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु दिये गये नोटिस में साफ और सही विवरण दिये जाये जो कि उक्त नियम में दिये गये हैं।

(ख) कोई ऐसे व्यक्ति यदि अधिशासी अधिकारी द्वारा साक्ष्य माँगा जाये तो साक्ष्य में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1817 के अन्तर्गत नस्टूमेन्ट ऑफ ट्रॉसफर यदि कोई हो, उसकी कापी और मूल रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें।

९—कर के आंशिक छूट या वापसी पाने के लिए ऐक्ट की धारा 151(2) के अधीन किसी भवन के मालिक जिसमें कई भवन हो कर निधारण के समय अधिशासी अधिकारी से प्रार्थना कर सकते हैं की उनकी कुल सम्पत्ति पर कर लगाते समय हर भवन का वार्षिक मूल्य अलग-अलग अकित कर लिया जायें। जब कोई ऐसा भवन जिसका वार्षिक मूल्य अलग से किया गया है 90 या उससे अधिक दिन लगातार खाली रहे तो उस वर्ष में उस काल का ऐक्ट की धारा 151(1) के अधीन सामान्य दर मुक्त या वापिस दे दिया जायेगा। मानो वह उस मकान पर अलग से लगाया गया था।

10—ऐकट की धारा 129 के अधीन 300 मीटर अर्द्ध ब्यास परिधि में कर लगाया जा सकेगा।

11—नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर की सीमा के अन्दर स्थिर अचल सम्पत्ति का कोई भी हस्तांतरण/बन्धक तब तक वैद्य नहीं माना जायेगा जब तक की उक्त 2 प्रतिशत कर की धनराशि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा न करा दी गयी हो।

12—सब रजिस्ट्रार के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा न करने की दशा में कार्यालय नगर पंचायत में नगद/चैक/बैंक ड्राफ्ट या बैंक में, पंचायतकोष कार्यालय में जमा की जा सकती है।

उ0प्र० नगरपालिका अधिनियम की धारा-1916-299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत छुटमलपुर जिला सहारनपुर यह आदेश देती है की उक्त कर अदा करने का दायित्व रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपनियम में वर्णित किसी एक अथवा सभी शर्तों का उलंघन करने पर अंकन एक हजार रुपये मात्र तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है यदि उलंघन जारी रहे अग्रेतर जुर्माना किया जा सकता है, जो प्रथम दोष सिद्ध दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी द्वारा अपराध करना जारी रखा गया है। 50.00 (पचास) रुपये प्रतिदिन हो सकता है।

13—नगर पंचायत छुटमलपुर के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं।

नगर क्षेत्र में टैंकर	केवल टैंकर रु0 300.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 500.00
नगर के बाहर टैंकर (4 वर्ग किमी0 सीमा तक)।	केवल टैंकर रु0 500.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 1000.00
मोबाइल टायलेट	केवल टायलेट रु0 1000.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 1500.00
मोबाइल टायलेट नगर के बाहर (4 वर्ग किमी0 सीमा तक)।	केवल टायलेट रु0 1500.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 2000.00
मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क	रु0 50.00	
जन्म प्रमाण पत्र शुल्क	रु0 100.00	
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु	सामान्य आवास रु0 30.00 प्रतिमाह	
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु	व्यावसायिक शुल्क प्रतिमाह 20 किग्रा0 से 50 किग्रा0 तक—80.00 रु0 50 किग्रा0 से 80 किग्रा0 तक—100.00 रु0 100 किग्रा0 से अधिक—150.00 रु0 1000.00 रु0 प्रति कार्यक्रम	
मैरिजहॉल		

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
छुटमलपुर, सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0म0र० मुख्यालय सूबेदारगंज में सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य कार्यालय अधीक्षक पद पर वर्ष 2004 से श्यामशंकर शर्मा कार्यरत हूं। 31 अक्टूबर, 2022 को रेल सेवा से अधिवार्षिता पर सेवा-निवृत्त हो जाऊंगा। सेवा पुस्तिका में मेरा नाम श्याम शंकर पुत्र बाल गोविन्द, निवासी छारिकापुर, पोस्ट दिलीपपुर, जिला प्रतापगढ़ दर्ज है।

श्याम शंकर शर्मा एवं श्याम शंकर दोनों मेरा ही नाम है। मेरे पहचान-पत्र, वेतन पर्ची, I-Pass, HRMS आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता में श्याम शंकर शर्मा पुत्र दर्ज है, जो गलत है। सही नाम SHIV SHANKAR

स्व0 बाल गोविन्द शर्मा (बी0जी0 शमी) दर्ज है यही सत्य है मुझे श्याम शंकर शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाता है।

श्याम शंकर शर्मा,
पुत्र श्री बाल गोविन्द शर्मा,
निवासी 314/ए, रेल गांव,
रेलवे कालोनी, सुबेदारगंज,
प्रयागराज।

सूचना

मेरे हाई स्कूल वर्ष 2019, रोल नं0 05046360 के अंक-पत्र में मेरे पिता का नाम SHANKAR YADAV

YADAV है। ARVIND KUMAR YADAV S/o SHIV SHANKAR YADAV मिश्र नेवरी, नियर टोल टैक्स बलिया। पटेल आयु 49 वर्ष डफरा, गढ़ियावा, पटटी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230124।

अरविन्द कुमार यादव,
पुत्र शिव शंकर यादव,
निवासी मिश्र नेवरी,
नियर टोल टैक्स, जनपद बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बैंक पास बुक, आधार कार्ड, बोटर आई०डी० (EPIC) में पिता जी का नाम अब्दुल हमीद है। मैं उत्तर मध्य रेलवे में कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत हूं। वहां के सेवा पुस्तिका में मेरे पिता जी का नाम अब्दुल अहमद लिखा है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। मैं अपने समस्त दस्तावेजों में अपने पिता जी का नाम अब्दुल हमीद करवाना चाहता हूं।

इस्ताखार अहमद,
पुत्र स्व० अब्दुल हमीद,
नि०-१९६, पूराबल्दी, कीडगंज,
प्रयागराज।

सूचना

फर्म मे० नानक चन्द्र कुन्दन लाल १/११/२४९/वी/१ विक्रम नगर जलेसर रोड टेडी बगिया, आगरा पत्रवली संख्या एजी-१२३६५ में दिनांक १२ अगस्त, २०२२ को श्री सजल सचदेवा पुत्र स्व० मदन लाल सचदेवा, निवासी ३० राम मोहन विहार दयालबाग, आगरा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये तदिनांक को श्री बृजेश तिवारी पुत्र स्व० उमेश चन्द्र तिवारी, निवासी १०४ एलोरा एन्कलेब दयाल बाग, आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये चर्तमान फर्म में भागीदार मोनिका तिवारी एवं बृजेश तिवारी हैं।

मोनिका तिवारी,
मे० नानक चन्द्र कुन्दन लाल,
१/११/२४९/वी/१ विक्रम नगर जलेसर,
रोड टेडी बगिया, आगरा।

सूचना

पार्टनरशिप के विघटन २७ सितम्बर, २०२२ को हुआ—

१—राम बचन निषाद आयु ४२ वर्ष बौराइ, अल्लाया, मछलीशहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-२२२२०१ और २—रामयश

पटेल आयु ४९ वर्ष डफरा, गढ़ियावा, पटटी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-२३०१२४। जबकि पार्टनर्स ने दिनांक २६ दिसम्बर, २०१७, पंजीकरण संख्या ५२६७/७-वी-१६४७०/१०-०१-२०१८ के तहत साझेदारी के एक विलेख के तहत खुद को एक व्यावसायिक फर्म में बनाया और नाम के तहत व्यवसाय किया और मेसर्स जय अम्बे वायरनिटींग इंडस्ट्रीज की शैली पंजीकृत पता प्लॉट नंबर जी-७, रोड नंबर १०, सीडा, सतहरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश-२२२२०२, अनुबंधों, शर्तों के अनुसार और उक्त साझेदारी को भंग कर दिया जायेगा और उक्त व्यापार और व्यवसाय को समाप्त कर दिया जायेगा।

रामयश पटेल,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नसरुल्लाह कंस्ट्रक्शन, ग्राम खरजरबा, पो० व जिला देवरिया, उ०प्र० नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक ०५ जुलाई, २०२१ से शाफिउल्लाह अंसारी, अब्दुल रौफ, जकाउल्लाह अंसारी व वसीउल्लाह अंसारी एवं नसीम अहमद जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली संख्या जी-२३१२ पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदार शफीउल्लाह अंसारी जी की मृतक दिनांक ०५ सितम्बर, २०२२ को हो चुकी है तथा साझेदारी डीड दिनांक ०६ सितम्बर, २०२२ से नसीम अहमद जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो गये हैं और नुरेश खातून एवं कलीमुल्लाह जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः नुरेश खातून, अब्दुल रौफ, जकाउल्लाह अंसारी व वसीउल्लाह अंसारी एवं कलीमुल्लाह जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

वसीउल्लाह,
साझेदार,
मेसर्स नसरुल्लाह कंस्ट्रक्शन,
ग्राम खरजरबा,
पो० व जिला देवरिया, उ०प्र०।

सूचना

मेसर्स श्री गोपाल ड्रेडिंग कंपनी २७ ए. न्यू मंडी, मुजफ्फरनगर कम पंजी० दि० ०५ जून, २००९ को उप निवंधक फर्म्स सोसाइटी सहारनपुर द्वारा हुआ था रजिस्ट्रेशन के समय फर्म्स में श्री आदित्य भरतिया, श्रीमति अनुश्री, अंशुमन भरतिया और श्री गौरंग भरतिया पार्टनर थे। दिनांक १० अगस्त, २०२२ की डीड अनुसार श्री अंशुमन भरतिया और श्री गौरंग भरतिया रिटायर्ड हो गये। फर्म में अब श्री आदित्य भरतिया और श्रीमति अनुश्री पार्टनर रह गए हैं फर्म का पता बदल कर अब २७ ए/१ नई मंडी, मुजफ्फरनगर २५१००१ हो गया है।

आदित्य भरतिया

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बालकेश (BALKESH) गलत दर्ज हो गया है सही नाम मंगला प्रसाद पुत्र छोटेलाल है (MANGLA PRASAD S/o CHHOTELAL) भविष्य में मुझे मंगला प्रसाद पुत्र छोटे लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय। मंगला प्रसाद पुत्र छोटे लाल करेहवा उपरहार प्रयागराज उ०प्र०।

मंगला प्रसाद।